द्वारा जीत के मुकाम तक पहुंचाने का यही रास्ता है। हमारे द्वारा लिये जाने वाला क्रांतिकारी भूमि-सुधार कार्यक्रम क्रांति के लिए अनुकूलताएं पैदा करेगी।

★ साम्राज्यवादी नयी उदारवादी नीतियों के खिलाफ विस्थापन आदि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरण समस्याओं पर उत्पीड़ित जनता को और कृषि संकट से तीव्र असंतुष्टि में रहे किसानों को संगठित कर बड़े पैमाने पर आंदोलनों में एकजुट करें! उन्हें लोकयुद्ध के साथ जोड़े! क्रांतिकारी व जनवादी संगठनों, शक्तियों, व्यक्तियों और व्यापक जनता को गोलबंद करते हुए व्यापक व मजबूत जन आंदोलन का निर्माण करें!

★ ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवाद के खिलाफ क्रांतिकारी शक्तियों, जनवादियों, प्रगतिशील शक्तियों, संगठनों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्षतावादियों को एकजुट कर मजबूत और जुझारू आंदोलन का निर्माण करें!

★ आदिवासी, दलित, महिला, धार्मिक अल्पसंख्यकों के समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर साझे मंचों पर जनता को संगठित करते हुए व्यापक जन आंदोलन का निर्माण करें!

★ प्रचंड-अवाकियान के नए संशोधनवाद सहित रंगबिरंगे संशोधनवाद, गांधीवाद, कानूनवाद, सुधारवाद, अर्थवाद, संसदवाद और उत्तर-आधुनिकतावाद जैसे बुर्जुआ सिद्धांतों का भण्डाफोड़ करें!

★ क्रांतिकारी इलाकों में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले सरकार के भाड़े के पुलिस, कमांडो और अर्धसैनिक बलों को और राज्य प्रायोजित प्रतिक्रांतिकारी संगठनों और गुटों के राज्यहिंसा के खिलाफ जनता और जनवादी ताकतों को गोलबंद कर संघर्ष करें! मजबूत जनप्रतिरोध आंदोलन का निर्माण करें!

★ कश्मीरी, नागा, मणिपुरी, असम आदि राष्ट्रीयताओं के अलग होने सहित आत्मनियंत्रण का अधिकार के लिए जारी आंदोलनों और अलग राज्य के लिए लड़ने वाले बोड़ोलैंड, गोर्खालैंड जैसे आंदोलनों के समर्थन में जनता को गोलबंद करें!

★ विश्व भर में जारी साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलनों के समर्थन में जनता को गोलबंद करें! उससे भारतीय क्रांति के लिए समर्थन एकत्रित करें!

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

केन्द्रीय कमेटी,

भाकपा (माओवादी)

11 अगस्त 2017

संदेश

जन-आधार को बढ़ाते हुए गुरिल्ला युद्ध को तेज व विस्तारित कर प्रतिक्रांतिकारी हमला-मिशन 2017 को दृढ़ता से प्रतिरोध कर परास्त करें!

पार्टी की 13वीं वर्षगांठ को 21 से 27 सितम्बर तक देश भर में क्रांतिकारी उत्साह और स्फूर्ति के साथ मनाएं!

पार्टी कमेटियों व सदस्यों, जनमुक्ति छापामार सेना के कमांडरों व योद्धाओं, पार्टी समर्थकों, क्रांतिकारी जन कमेटियों के नेतृत्व व सदस्यों, क्रांतिकारी जनसंगठनों व क्रांतिकारी जनता को केन्द्रीय कमेटी का आह्वान!

केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

लोकयुद्ध का आंकलन किया जाना चाहिए। उसमें अपने अनुभवों का सही रूप से संग्रहण व संश्लेषण कर उससे सकारात्मक और नकारात्मक सबक सीखना होगा। हमें अधिक सफलताएं हासिल करते हुए आगे बढ़ने के लिए वर्गदिशा–जनदिशा पर निर्भर होकर माकूल कार्यनीतियां और कार्यभार अपनानी होगी।

मिशन–2017 के तहत क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में जनता और जनवादियों पर शोषक–शासक वर्गों द्वारा जारी युद्ध के खिलाफ स्थानीय स्तर से लेकर केन्द्रीय स्तर तक जनवादी शक्तियों को गोलबंद कर संयुक्त मोर्चों का गठन करना होगा। पहले से मौजूद मंचों को सक्रिय करना होगा।

★ बोल्शेवीकरण अभियान के अनुभवों के आधार पर पार्टी का लगातार बोल्शेवीकरण करें!

हमारी पार्टी द्वारा संचालित बोल्शेवीकरण अभियान प्रत्याशित दिशा में एक हद तक अनुकूल परिणाम दे रही है। इस अभियान से मिले अनुभवों के आधार पर लगातार व्यवहार जारी रखने की जरूर है ताकि पार्टी का बोल्शेवीकरण कर सके। इसे ध्यान में रखकर ऊपर से नीचे तक पार्टी के कैडर को दृढ़संकल्प के साथ अपना कार्य जारी रखना चाहिए। जहां इस अभियान पूरा नहीं हुआ, वहां सर्वहारा वर्ग के स्फूर्ति के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कराने की योजना बनानी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए।

★ बदलती सामाजिक परिस्थितियों के मुताबिक लोकयुद्ध के कार्यनीतियों को विकसित करने के लक्ष्य से सभी राज्य/स्पेशल एरिया/स्पेशल जोनों में सामाजिक जांच–पड़ताल और वर्ग विश्लेषण करें! सही कार्यनीतियां बनाकर ठोस परिस्थितियों के मुताबिक सृजनात्मक तरीके से जोड़कर लोकयुद्ध को आगे बढ़ाएं!

★ दुनिया को हिला देने वाली रूसी बोल्शेविक क्रांति की शताब्दी वर्षगांठ समारोह और अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के महान मार्क्सवादी शिक्षक कार्ल मार्क्स की द्वि शताब्दी जयंती उत्सवों को बहुत ही क्रांतिकारी जोशखरोश और स्फूर्ति के साथ मनाएं!

★ नवजनवादी क्रांति के मुख्य सार के रूप में रहे क्रांतिकारी भूमि–सुधारों पर अपना ध्यान केंद्रित करें!

क्रांतिकारी भूमि–सुधार कार्यक्रम जनवादी क्रांति का मुख्य सार है। वह व्यापक जनता में मौजूद बहुसंख्यक किसान जनता को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर मुक्ति दिलायेगी। किसान जनता से दृढ़ व जूझारू मदद पाने के लिए, नवजनवादी क्रांति को दीर्घकालीन लोकयुद्ध

कम्युनिकेशन टॉवर निर्माण करने आदि का निर्णय लिया गया है। घोषणा किया गया है कि अब माओवादियों का सफाया अभियान का कमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, देश की आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के. विजय कुमार संभालेंगे। इस बैठक में लिए गए निर्णयों में बहुत ही महत्वपूर्ण है सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का निर्णय। ये सब आगामी 2019 में होने वाले संसदीय चुनावों के पहले योजनाबद्ध तरीके से हमारी पार्टी के क्रांतिकारी नेतृत्व और क्रांतिकारी आत्मगत शक्तियों का उन्मूलन कर भारतीय क्रांति को हराने के लक्ष्य को ही उजागर कर रहे हैं। इस लक्ष्य के अंदर ही मिशन-2017 बहुत ही आक्रामक रूप से खूनी हमलों के साथ शुरू हो गयी है। आगामी दो साल भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए गम्भीर चुनौती के रूप में रहेगी।

जनान्दोलनों को दबाने के लिए लूटी शासक वर्ग कितना भी क्रूर दमन नीति चाहे क्यों न अपनाएं, इतिहास के क्रम में यह बार-बार साबित हुआ है कि वे आखिर में विफल होते है। इस अनुभव के साथ क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया करने के लक्ष्य से भारत के शासक वर्गों द्वारा चलाये जा रहे मिशन-2017 को हराने और ऊपर से नीचे तक पार्टी नेतृत्व को बचाते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने को फौरी कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए। जन-आधार को बढ़ाते हुए वर्गदिशा-जनदिशा पर निर्भर होते हुए जनयुद्ध-छापामार युद्ध का संचालन करना चाहिए। इसमें जीत हासिल करना है तो, यथासंभव हमारे शक्तियों को बचाना होगा। दुश्मन के कमजोरियों को इस्तेमाल कर, मौका मिलने के तुरंत बाद पीएलजीए बलों को केन्द्रीकृत कर दुश्मन के अकेली इकाइयों पर या उन्हें विभाजित कर हमला कर सफाया करना होगा, हथियार जब्त करना होगा। इसके लिए छापामार युद्ध नियमों व उसूलों - गुप्तता, तेजगति व दृढ़संकल्प तथा स्थानांतरण के आत्मरक्षात्मक व आक्रामक कार्यनीतियों को पहलकदमी के साथ अमल करेंगे। छापामार युद्ध को तेज व विस्तारित करेंगे। आत्मरक्षा, जन-आधार को बढ़ाने, आत्मगत शक्तियों को बढ़ाने व मजूबत करने, आंदोलन को विस्तारित करने, आदि फौरी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आत्मबलिदान की चेतना के साथ संघर्ष करते हुए जनयुद्ध को और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए निम्न लिखित कार्यभारों को लेकर प्रयासरत होंगे :

कार्यभार

★ मिशन-2017 को परास्त करें! क्रांतिकारी आंदोलन को कठिन दौर से उबारने के लिए एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस द्वारा निर्देशित केंद्रीय कार्यभार को अमल करने के तहत लोकयुद्ध में अधिक सफलताएं हासिल करने की लक्ष्य से आगे बढ़ें!

पिछले साल भर में शोषक-शासक वर्गों द्वारा जारी मिशन-2016 और मिशन-2017 के खिलाफ हमारी पार्टी के नेतृत्व में संचालित की गयी

संदेश

जन-आधार को बढ़ाते हुए गुरिल्ला युद्ध को तेज व विस्तारित कर प्रतिक्रांतिकारी हमला-मिशन 2017 को दृढ़ता से प्रतिरोध कर परास्त करें!

पार्टी की 13वीं वर्षगांठ को 21 से 27 सितम्बर तक देश भर में क्रांतिकारी उत्साह और स्पूर्ति के साथ मनाएं!

सर्वप्रथम हमारी पार्टी की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी विभिन्न स्तरों के पार्टी कमेटियों व सदस्यों, जनमुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) के कमांडरों व योद्धाओं, पार्टी समर्थकों, क्रांतिकारी जन कमेटियों (आरपीसी) के नेतृत्व व सदस्यों, क्रांतिकारी जनसंगठनों व क्रांतिकारी जनता को तहेदिल से क्रांतिकारी अभिवादन पेश करती है। उसी तरह हमारी पार्टी के नेतृत्व में देश में जारी जनयुद्ध के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने वाले विभिन्न देशों के माओवादी पार्टियों व संगठनों को इस अवसर पर हमारी सीसी क्रांतिकारी अभिवादन पेश करती है।

प्रिय कामरेडो!

हमारी पार्टी और क्रांतिकारी जनता के लिए 21 सितम्बर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 21 सितम्बर 2004 को देश के दो मुख्य क्रांतिकारी धाराओं का विलय होकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन हुआ। हमारी केन्द्रीय कमेटी पार्टी की 13वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर जन-आधार को बढ़ाते हुए गुरिल्ला युद्ध को तेज-विस्तार कर प्रतिक्रांतिकारी हमला-मिशन 2017 को दृढ़ता से प्रतिरोध करने व परास्त करने के लक्ष्य से 21 से 27 सितम्बर तक देश भर में वर्षगांठ समारोह क्रांतिकारी जोशखरोश और स्पूर्ति के साथ मनाने विभिन्न स्तर के पार्टी कमेटियों व सदस्यों, जनमुक्ति छापामार सेना के कमांडरों व योद्धाओं, पार्टी समर्थकों, क्रांतिकारी जन कमेटियों के नेतृत्व व सदस्यों, क्रांतिकारी जनसंगठनों व क्रांतिकारी जनता को आह्वान करती है।

हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन का पूरी तरह सफाया करने के लक्ष्य से दुश्मन द्वारा समूचे देश में जारी प्रतिक्रांतिकारी दमन अभियान के तहत नीलम्बूर जैसे झूठी मुठभेड़ों में; दुश्मन के बलों के साथ हुई रामगुड़ा

(आंध्रा-ओड़िशा बार्डर), बुढ़ा नदी (बिहार-झारखण्ड) जैसे मुठभेड़ों व कोवर्ट ऑपरेशनों में, पीएलजीए बलों पर दुश्मन द्वारा घात लगाकर किये गये हमलों में; बिहार-झारखण्ड में टीपीसी, जेजेएमपी जैसे प्रतिक्रांतिकारी हत्यारे गिरोहों के हमलों में; पुलिस, कमांडो व अर्धसैनिक बलों पर हमारी पीएलजीए बलों द्वारा बहुत ही साहसिक ढंग से चलाई गई हमलों में; बृद्धावस्था, अस्वस्थता, सर्पदंशण आदि कारणों से देश भर में पिछले साल लगभग हमारे 180 प्रिय कामरेडों और जनता ने अपनी अनमोल जानें अर्पित की हैं। इनमें 50 से ज्यादा महिला कार्यकर्ता और ग्रामीण महिला शामिल हैं।

इस साल भारतीय क्रांति के दो नेता व हमारी पाटी के केन्द्रीय कमेटी व पोलिट ब्यूरो के सदस्य कामरेड नारायण सान्याल (बिजय दा) (80), केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कामरेड कुप्पु देवराज (रमेश, योगेश) (62) के शहादत क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति है। गंभीर अस्वस्थता के इलाज के लिए कोजिकोड जा रहे कामरेड्स देवराज और अजिता को 'ऑपरेशन ब्रह्मगिरि' के तहत गिरफ्तार करने के बाद दुश्मन के केन्द्रीय व राज्य खुफिया अधिकारियों द्वारा तीव्र यातना देकर 24 नवम्बर को केरल राज्य के नीलम्बूर जंगल इलाके में गोलियों से भून डाला। कामरेड नारायण सान्याल केन्सर बीमारी से 16 अप्रैल को कोलकता में शहीद हुए। राज्य कमेटी के सदस्य बिहार-झारखण्ड (बीजे) में वरिष्ठ कामरेड रघुनाथ महतो; आंध्र-ओड़िशा बार्डर (एओबी) में कामरेड्स प्रसाद व दया; पश्चिमी घाटियों (डब्ल्युजी) में कामरेड अजिता (कावेरी) शहीद हुए। उसी तरह रीजनल कमेटी के सदस्य कामरेड संग्राम मुर्मू (बीजे), जिला कमेटी के सदस्य एओबी में कामरेड्स प्रभाकर, किरण; बीजे में कामरेड यतीन (कोयल-शंख), शैलेश, अजित यादव; दण्डकारण्य (डीके) में कामरेड्स जगत (पश्चिम बस्तर), पाली (दरभा), कैलाश (पूर्वी बस्तर), सबजोनल कमेटी सदस्य कामरेड नागेन्द्र यादव (बीजे); एरिया कमेटी के सचिव कामरेड शमीला (आरकेबी, डीके); 38 एरिया कमेटी व प्लाटून पार्टी कमेटी के सदस्य (इसमें पीएलजीए के कई कामरेडों ने दस्ता/सेक्शन व प्लाटून कमांडर/डिप्टी कमांडर के रूप में काम किये); तीन ग्राम पार्टी कमेटी व क्रांतिकारी जन कमेटियों के नेताओं, पांच जन मिलिशिया कमांडरों, तीन जनसंगठनों के नेताओं सहित दसियों संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पीएलजीए व जन मिलिशिया के योद्धा, क्रांतिकारी समर्थक व जनता आदि जनयुद्ध में शहीद हुए हैं।

महिला कैडरों में एओबी के कामरेड्स ममता, लता (भारती), कांता नाना

करना अंत में जवाबी हमले करने की क्षमता पर चोट पहुंचाता है' के उपदेश दिया है। यह आक्रामकता केवल फौजी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होगा। यह प्रधान रूप से वैचारिक क्षेत्र से संबंध रखता है। पहले से ही राज्ययंत्र के पूरे समर्थन के साथ भगवा सेना ने यह हमला शुरू किया है। इसके तहत उसने यह भी घोषणा किया है कि इसके तहत 'सफेद-पोशी' नक्सलवादियों के नाम पर मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा जनवाद-प्रेमियों को निशाना बनायेगी। यानी यह हमला केवल माओवाद पर ही नहीं है। समूचे प्रगतिशील विचारों पर, यहां तक की उदारवादी जनवादी विचारों पर भी जारी है। उनके इस आक्रामकता को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मौजूदा नाममात्र 'संसदीय जनवाद' का भी काम खत्म हो गया है।

देश में हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी लोकयुद्ध कई ज्वार-भाटों, उतार-चढ़ाओं, कष्ट-तकलीफों, मोड़ों-करवटों से उबरते हुए आगे बढ़ने के साथ-साथ देश की जनता के सामने एक वैकल्पिक क्रांतिकारी रास्ता विकसित हो रहा है। इसे भारतीय शोषक-शासक सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। साम्राज्यवादी प्रायोजित प्रतिक्रांतिकारी एलआइसी रणनीति के साथ क्रांतिकारी आंदोलन का पूरी तरह उन्मूलन करने की योजना बनाएं हैं। इसके तहत 8 मई की बैठक में एक तरफ भारतीय सेना को हमारे आंदोलन के इलाकों में तैनात करने का सवाल ही नहीं है - कहते हुए, दूसरी तरफ सेनाधिकारियों के मार्गदर्शन में आंदोलन का सफाया करने की योजनाएं तय कर रहे हैं। इसके तहत सीआरपीएफ (एल.डब्लु.इ.) के केन्द्रीय जोनल कमान केन्द्र को कोलकाता से रायपुर स्थानांतरित किया गया है। एकीकृत कमानों का जिला स्तर तक गठन कर कार्यनीतिक-कार्रवाहिक स्तर पर कमानों को मजबूत कर रहे हैं। राज्य व केन्द्रीय बलों के बीच समन्वय में बेहतरी लाने के लिए एक कमेटी का गठन कर रहे है। रायपुर में स्थित नक्सल ऑपरेशनों के पुलिस महानिदेशक (डीजी) के कार्यालय को जगदलपुर (बस्तर) स्थानांतरित किया जा रहा है। खुफिया तंत्र को और विस्तार कर मजबूत कर रहे है। विशेषकर, ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया तंत्र को मजबूत कर रहे है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था (यूएवी-ड्रोन, उपग्रह, जीपीएस, थर्मल इमेजिंग, इनफ्रारेड तकनीक, सीसीटीवी केमरा, राडार आदि) के जरिए तत्काल खुफिया सूचना (रियल-टाइम इंटलिजेंस) प्राप्त करने के साथ ऑपरेशनों में इस व्यवस्था को मजबूती से इस्तेमाल करने, वायुसेना को ऑपरेशनों में भी इस्तेमाल करने (कमांडों बलों को हेलीकॉप्टरों से तैनात कर हमले करने के साथ-साथ, हेलीकॉप्टरों से ही स्ट्राफिंग यानी गोलीबारी करने, ड्रोन हमले करने) जा रहे है। पुलिस बलों को नई किस्म की प्रशिक्षण देने, सुकमा और बीजापुर में काउण्टर-इंसर्जेंसी स्कूल स्थापित करने, केन्द्रीय-राज्य बलों के बीच समन्वय बढ़ाने जा रहे है। आंदोलन के इलाकों में अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द सड़कों का निर्माण पूरा करने, और कुछ

मुजाहिद्दीन संगठन के बुरहान वानी की हत्या के बाद तेज होकर वर्तमान कश्मीर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का उभार अभी भी जारी है। कश्मीरी जनता 'पत्थरों' से भारतीय सेना व अर्धसैनिक बलों के खिलाफ संघर्ष करते हुए केन्द्र-राज्य सरकारों को परेशानी में डाल रही हैं। इस पूरे वर्ष में छात्र-छात्राओं ने भी बहुत ही जुझारू रूप से इसमें भाग लिया हैं। उत्तर-पूर्व के राष्ट्रीय मुक्ति संगठन फिर से संगठित होकर और संयुक्त मोर्चा बनाकर भारतीय विस्तारवादियों के खिलाफ लड़ रही हैं। मोदी सरकार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के आंदोलनकारियों का, खासकर कश्मीर में बड़े पैमाने पर सफाया करते हुए उन आंदोलनों का उन्मूलन करने के लिए तीव्र दमन लागू कर रही है। हाल ही में 'धारा 35ए' जिसे कश्मीर के आत्मनियंत्रण के अधिकार के लिए आखिरी आधार के रूप में बताया जा रहा है, को रद्द करने के लिए भी उतारू है। इसके खिलाफ कश्मीर के लोगों में तीव्र आक्रोश उभर रहा है। वहां के राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। गोर्खालैंड के लिए 57 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। राज्य सरकार बड़े पैमाने पर पुलिस बलों को तैनात करने, सेना को बुलाने, निषेधाज्ञा लगाने, गिरफ्तारियां करने, आंसू गैस के गोले दागने, गोलीबारी कर लोगों की हत्या करने के बावजूद वीर गोर्खा जनता जुझारू संघर्ष कर रही हैं।

देश में महिलाओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रकाश में आए आंकड़े के मुताबिक देश में प्रत्येक तीन मिनट पर एक महिला पर हिंसा हो रहा है। दहेज प्रथा से प्रत्येक वर्ष 8 हजार महिलाओ की आहुति हो रही हैं और 50 हजार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, 40 हजार महिलाओं को ला पता कर रहे हैं। एसिड हमले, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति में धकेलने, भ्रूणहत्या व छोटी उम्र की बच्चियों की हत्या, आदि सामंती व साम्राज्यवादी संस्कृति के बड़े पैमाने पर फलने-फूलने के कारण ही हो रही हैं। इनके खिलाफ महिलाओं और जनवादियों का आंदोलन देश भर में जारी है।

प्रिय कामरेडो!

हमारे जन छापामारों द्वारा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मार्च व अप्रैल महीनों में अंजाम दिए गए दो अलग-अलग एम्बुशों में 37 सीआरपीएफ जवानों का सफाया किया गया और 10 को घायल किया गया। इस पृष्ठभूमि में 8 मई को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री के अध्यक्षता में माओवादी आन्दोलन चलने वाले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस उच्च अधिकारियों व जिला कलेक्टरों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें उन्होंने 'हर एक पहलू में भी आक्रामकता होनी चाहिए, आत्मरक्षात्मक तरीके से व्यवहार

जैसी पार्टी के वरिष्ठ कामरेड, कामरेड्स बुदरी, मंजुला (उंगी), टुबरी (कोरापुट); डीके के कामरेड्स हेमला अंजु (दक्षिण बस्तर), रम्मो (आरकेबी), दरभा में कामरेड्स सुक्की, जोगी, पूर्वी बस्तर में कामरेड्स जगबत्ति यादव (सोनी), राजबत्ति, माड में कामरेड्स माली, करूणा; बीजे में कामरेड अनुप्रिया (कोयल-शंख) आदि दुश्मन के बलों के साथ हुई अलग-अलग मुठभेड़ों में वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हुई। कुछ महिला कामरेडों को मुठभेड़ों में घायल अवस्था में पकड़कर या घर के पास पकड़कर सामूहिक बलात्कार कर हत्या की गयी। इनमें कुछ ग्रामीण महिलाएं भी शामिल है।

भारतीय क्रांति के महान नेता, पार्टी के संस्थापक व शिक्षक कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी सहित नक्सलबाड़ी के क्रांतिकारी सशस्त्र किसान संघर्ष से लेकर अब तक शहीद हुए हजारों वीर शहीदों को याद करते हुए, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर जनयुद्ध में लक्ष्य हासिल करने के लिए दुश्मन के साथ साहसिक ढंग से लड़ते हुए, पिछले साल भर में जान की कुरबानी देने वाले सभी वीर योद्धाओं में से हर एक के नाम को याद करते हुए हमारी पार्टी के 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर क्रांतिकारी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर वीर शहीदों के परिवारों व मित्रों को संवेदना व्यक्त करते हुए, केन्द्रीय कमेटी उन सभी को हर संभव मदद देने का वादा करती है।

इस अवसर पर, विश्व समाजवादी क्रांति को सफल बनाने के लक्ष्य से विभिन्न देशों में माओवादी पार्टियों, संगठनों व ग्रुपों के नेतृत्व में जारी आंदोलनों में शहीद हुए वीर योद्धाओं को हमारी सीसी क्रांतिकारी जोहार अर्पित करती है।

पिछले साल केंद्र-राज्य सरकारों द्वारा लागू साम्राज्यवाद-परस्त, जनविरोधी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण नीतियों के खिलाफ, खासकर साम्राज्यवादियों के बल पर फासीवादी शासक वर्गों द्वारा अत्यंत बर्बर एवं क्रूर तरीके से जारी ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ हमारी पार्टी के नेतृत्व में पार्टी कतारों, पीएलजीए योद्धाओं, क्रांतिकारी जन कमेटियों, क्रांतिकारी जन संगठनों, देश की जनता खासकर, संघर्षरत इलाकों की जनता द्वारा संचालित प्रतिरोधात्मक युद्ध में अपने जान न्योछावर करने वाले वीर योद्धाओं का आत्मबलिदान बहुत ही मूल्यवान, आत्मत्यागी, आदर्शणीय और अनुसरणीय है। जहां असमानता, भेदभाव व मानव का मानव द्वारा शोषण असंभव हो, एक ऐसी नयी व जायज समाज के लिए उन्होंने अपनी अनमोल जानों की कुरबानी दी।

हमारी पार्टी की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहीदों द्वारा दर्शाये गए राह पर आगे बढ़ने और एक नयी दुनिया की स्थापना हेतु उनके अरमानों को पूरा करने के लिए दृढ़संकल्प व आत्मबलिदान की चेतना के साथ साहसिक ढंग से संघर्ष करने की कसम खाते हैं। वीर शहीदों के कुरबानियों द्वारा पिछले साल भर में दुश्मन के दमन अभियानों का मुकाबला करते हुए हासिल सफलताओं और पार करने वाली कमजोरियों को हमारी पार्टी के कतारों, पीएलजीए बलों और व्यापक जनता के सामने रखते हैं। लोकयुद्ध में उन सब की सक्रिय और जुझारू भूमिका को बढ़ाने का प्रयास करने का प्रण लेते हैं।

पिछले एक साल में हमारी सफलताएं:

1) शोषक-शासक वर्गों के प्रतिक्रांतिकारी युद्ध को प्रतिरोध करते हुए जनयुद्ध को कायम रख पाये हैं : केन्द्र में भाजपा की मोदी के नेतृत्व में राजग (एनडीए) सरकार सत्ता में आकर तीन साल पूरे होने और कई राज्यों में भाजपा/एनडीए सरकारों के गठन के साथ-साथ समूचे देश में ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवादी हमला तेज हो गया है। इसके तहत साम्राज्यवादी व सामंतवादी शोषण के खिलाफ दृढ़ता से लड़ने वाली हमारी पार्टी व उसके नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन का पूरी तरह सफाया करने के लिए एलआईसी रणनीति के तहत मिशन 2016 और मिशन 2017 के नाम पर पिछले साल सभी क्रांतिकारी इलाकों में सफेद आतंकी अभियान और तेज हो गया है। भाड़े के फासीवादी पुलिस, कमांडो व अर्धसैनिक बल पीएलजीए बलों पर हमलों व झूठी मुठभेड़ों में क्रांतिकारियों व जनता की हत्या तेज की है। सिर्फ 2017 में ही अब तक 78 क्रांतिकारियों व जनता की हत्या की गयी है। गांवों पर बड़े पैमाने पर हमले करते हुए लोगों के संपत्ति और फसलों को तहस-नहस किया है। घरों में आग लगाया है। बिहार, झारखंड राज्यों में हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्पत्ति का कुर्की जब्ती कर रहे हैं। आंदोलन को कुचलने के लिए महिलाओं का बलात्कार एक हथियार के रूप में बेरोकटोक इस्तेमाल कर रहे हैं। बुर्जुआ सुधारों को बड़े पैमाने पर लागू करते हुए क्रांतिकारी जनता में फूट डालने की कोशिशें कर रहे हैं। संघर्षरत इलाकों में राज्य आतंक के बारे में बाहर दुनिया के सामने ले जाने की प्रयास करने वाले पत्रकारों पर, विरोध जताने वाले जनवादी बुद्धिजीवियों, सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, महिला संगठन के कार्यकर्ताओं, प्राध्यापकों, छात्रों और विपक्षी पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं तथा सरकारी उच्च अधिकारियों पर भी फासीवादी दमन चला रहे हैं। इन्हें 'माओवादी,' 'राजद्रोही' के

देशभक्ति शक्तियां विभिन्न मंचों पर गोलबंद हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर साहारनपुर, गुजरात के उना, राजस्थान के अल्वर तक जारी इन हमलों के परिप्रक्ष्य में दलितों, मुसलमानों के साथ-साथ आदिवासी और अन्य उत्पीड़ित जातियों के शक्तियां उना में गोलबंद होकर हिन्दू धर्मोन्माद का मुकाबला करने के लिए कार्ययोजना बनायी हैं। मजदूर, किसान, छात्र, युवा, महिला, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बेरोजगार लड़ रहे हैं। दिल्ली में रामजस कॉलेज में प्रगतिशील छात्रों पर हिंन्दूत्ववादी संघ परिवार के हमलों के खिलाफ 14 राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बड़े पैमाने पर हुए छात्रों-प्राध्यापकों का एकताबद्ध आंदोलन इसका एक उदाहरण के रूप में रहेगा।

मोदी सरकार के मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ वामपंथी ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में देश भर में पिछले साल सितम्बर महीने में 15 करोड़ से ज्यादा मजूदरों ने आम हड़ताल कर सफल बनाया। इस साल फरवरी 28 को 10 लाख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने श्रम कानूनों में सुधारों के साथ-साथ आउटसोर्सिंग जैसे अन्य जनविरोधी सरकारी नीतियों के खिलाफ बंद का आयोजन किया। जुझारू रूप से जारी मजदूर आंदोलनों को नेतृत्वविहीन कर चोट पहुंचाने का शासक वर्ग कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ही मारुती सुजुकी कंपनी में मजदूर वर्ग के नेतृत्व को जेलों में ठूसकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। इसे मजदूर वर्ग को एकजुटता से मुकाबला करने की जरूरत है।

केन्द्रीय व राज्य सरकारों के किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में किसान विभिन्न तरीकों से लड़ रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित कई राज्यों में बैंक ऋणों की माफी, समर्थन मूल्य, सब्सिडियों की मांग करते हुए किसान जुझारू संघर्ष कर रहे हैं। इनपर सरकारें अपनी सशस्त्र बलों का को प्रयोग कर क्रूर दमन लागू कर रही हैं। इस जनविरोधी, निरंकुश नीतियों का विरोध करने वाले संगठनों और बुद्धिजीवियों पर 'उपा' आदि फासीवादी कानूनों का प्रयोग कर जेलों में ठूस रही हैं। देश में लड़ रहे हर एक उत्पीड़ित वर्ग, तबका, राष्ट्रीयता तीव्र दमन का शिकार है।

राष्ट्रीयताओं के अलग होने सहित आत्मनियंत्रण का अधिकार के लिए, बोडो और गोर्खा लोग अलग राज्य के लिए कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर और असम के जनता लड़ रही हैं। पिछले साल जुलाई में भारतीय फौज द्वारा हिजबुल

हाल ही में हिन्दूत्व फासीवादी मोदी के नेतृत्व में संघ परिवार के इस गुट ने 'करेंगे, कर के रहेंगे' का नारा देकर यह संदेश दिया है कि देश में बदलती परिस्थितियों के मुताबिक सिद्धांत को बदलना होगा, 2022 तक आतंकवाद, सांप्रदायिकतावाद और जातिवाद का उन्मूलन करना होगा, देश के विकास के लिए 'नये भारत का निर्माण' करना होगा, देश में गरीबी, कुपोषण, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना होगा और 'संकल्प से सिद्धि' के नाम से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के नाम पर बड़े नोटों को रद्द कर आम आदमी के पूरे पैसे जबरन व बड़े पैमाने पर लूट कर बैंकों में जमा करवा कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों व बड़े नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के हितों को पूरा करने वाला यह गुट; साम्राज्यवाद-परस्त भूमण्डलीकरण नीतियों को लागू करते हुए गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों, किसान, छोटे व्यापारियों-पूंजीपतियों के जिन्दगियों को दूभर करने वाला यह गुट बहुत ही भ्रामक नारों और योजनाओं से लोगों को और एक बार धोखा देने का प्रयास कर रहा है। दरअसल आज इस गुट द्वारा शुरू किये गये इस अभियान का प्रधान लक्ष्य - हिन्दू फासीवादी राष्ट्र की स्थापना; माओवादी आंदोलन और कश्मीर व उत्तर-पूर्व के राष्ट्रीयताओं के मुक्ति आंदोलनों का उन्मूलन करना; मुसलमान व इसाई आदि धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा आदिवासी शक्तियों का उन्मूलन करना; ब्राह्मणवादी हिन्दू फासीवाद का मुकाबला करने वाले शक्तियों, सभी क्रांतिकारी व जनवादी शक्तियों, उत्पीड़ित जाति के लोगों व आदिवासियों आदि उत्पीड़ित तबकों का आत्मसमर्पण करवाना; विपक्षी राजनीतिक पार्टियों पर चोट पहुंचाने के सिवा और कुछ नहीं है।

केन्द्र में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आसीन होने के कारण संघ परिवार की आक्रामकता को और बढ़ावा मिला है। पहले भारत को कांग्रेसविहीन करने का दावा करने वाला मोदी, वर्तमान देश में सभी संसदीय विपक्ष को मिटाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। विभिन्न राज्यों में विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व में मौजूदा सरकारों को उखाड़ना, उनके नेताओं को बहला-फुसलाकर, डरा-धमकाकर आत्मसमर्पण करवाना, खरीदना, अवसरवादी गुप्त समझौते करना, जो समर्पण नहीं करते उनपर खुफिया तंत्र का इस्तेमाल कर और पुलिस बलों को प्रयोग कर हमले करवाना, झूठे मामलों में फंसाना आदि कर रहा है।

देश के लोगों पर दिन ब दिन बढ़ते ब्राह्मणवादी हिन्दू फासीवादी हमले का मुकाबला करने के लिए समूचे देश में क्रांतिकारी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और

नाम पर क्रूर 'उपा' आदि दमनकारी कानून के तहत गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस रहे हैं। विभिन्न बुर्जुआ न्यायालयों द्वारा क्रांतिकारियों व क्रांतिकारी जनता को, उन्हें समर्थन देने वाले बुद्धिजीवियों, जनवादी शक्तियों, व्यापारियों को लम्बे अवधि के कठिन कारावास और फांसी के सजा सुना रहा हैं। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन जारी रहनेवाले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओड़िशा, पश्चिम बंग, असम, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में सफेद आंतक मचा रहे हैं।

दुश्मन के सफेद आतंक के खिलाफ इस साल हमारी पार्टी के नेतृत्व में जन प्रतिरोध, पीएलजीए व जन मिलिशिया बलों का प्रतिरोध जारी है। गांवों पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा जारी विध्वंसकाण्ड, आम जनता का हत्याकांड, झूठी मुठभेड, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार व हत्या के खिलाफ कानूनी-गैरकानूनी रूपों में लोग अपने-अपने जगह पर प्रतिरोध कर रहे हैं। जनमुक्ति छापामार सेना द्वारा क्रांतिकारी जनता के सहयोग से कार्यनीतिक जवाबी हमला अभियानों व कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। मुंगारुगुम्मि-सुंकी एम्बुश (कोरापुट, ओड़िशा), भावे-1, भावे-2 (राजनांदगांव, छत्तीसगढ़), चेरली एम्बुश (बीजापुर, छत्तीसगढ़), तुमड़ीवाल एम्बुश (कोण्डागांव, छत्तीसगढ़), हरियल एम्बुश (बीजापूर, छत्तीसगढ़), कोत्ताचेरुवु-भेज्जी एम्बुश (सुकमा, छत्तीसगढ़), बुर्गुम पहाड़ काण्उटर हमला (दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़), बुरकापाल एम्बुश (सुकमा, छत्तीसगढ़), कारमपल्ली माइनप्रूफ गाड़ी पर एम्बुश (गढ़चिरोली, महाराष्ट्र), पोखरी एम्बुश (कंधमाल, ओड़िशा), तोंडामरका काउण्टर हमला (सुकमा, छत्तीसगढ़), चिन्ना बोड़केल एम्बुश (सुकमा, छत्तीसगढ़) जैसे कार्रवाइयों में दुश्मन के बलों पर उल्लेखनीय स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया। क्रांतिकारी इलाकों में युद्धसामग्री पहुंचने से हमें वंचित कर दुश्मन द्वारा सप्लाई के सभी मार्गों को बंद कर देने की स्थिति में स्थानीय संसाधनों और सीमित स्रोतों के साथ छापामार युद्ध को संचालित करते हुए पिछले 10 महीनों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, एओबी, तेलंगाना, पश्चिम बंग, पश्चिमी घाटी आदि के विभिन्न छापामार जोनों और लाल प्रतिरोध इलाकों में किये गये लगभग 170 छापामार हमलों को पीएलजीए ने अंजाम दिया। इन छापामार हमलों में 85 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गये और लगभग 140 घायल हुए। लगभग 80 जनदुश्मन, जनविरोधी राजनेता, प्रतिक्रांतिकारी गद्दार और मुखबिर-कोवर्ट मारे गये। पीएलजीए द्वारा संचालित इन कार्यनीतिक जवाबी कार्रवाइयों ने, विशेषकर बुरकापाल एम्बुश ने, शोषक-शासक वर्गों में

खलबली पैदा की।

2) जन आंदोलनों और संयुक्त मोर्चा के गतिविधियों में वृद्धि : आंदोलन के सभी इलाकों में संयुक्त मोर्चा के गतिविधियों में वृद्धि हुई है। विस्थापन समस्या के खिलाफ, राज्यहिंसा के खिलाफ, ऑपरेशन ग्रीनहंट के खिलाफ, ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवाद के खिलाफ हमारी पार्टी द्वारा चलाये जा रहे संयुक्त मोर्चा के गतिविधियों में आदिवासी व गैरआदिवासी किसान, छात्र, बुद्धिजीवी, मजदूर, महिला और कलाकार लड़ रहे हैं। कामरेड कुप्पु देवराज और कामरेड अजिता की झूठी मुठभेड़ के खिलाफ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जनसंगठनों के नेतृत्व में उत्पीड़ित जनता बड़े पैमाने पर गोलबंद होकर पुलिस बलों के खिलाफ जुझारू संघर्ष किया। राज्यहिंसा, ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ देश भर में कई रैलियां, आम सभाएं और आंदोलन चलाई गयी। संघर्षरत इलाकों में सशस्त्र प्रतिरोध, कई बार बंद और विरोध दिवस आयोजन किया गया। गोरक्षा के नाम पर दिन ब दिन तेज होती जारी रही ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवाद के खिलाफ देश भर में लोग संघर्षरत हैं। इन आंदोलनों का हमारी पार्टी ने समर्थन कर रही है। क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में संघ परिवार द्वारा चलाए जा रहे फासीवादी कार्रवाइयों के खिलाफ पार्टी लोगों को गोलबंद कर रही है। संयुक्त मोर्चों का गठन कर लड़ रही है। इन संघर्षों से बड़े पैमाने पर लोग, खासकर नयी पीढ़ी के युवा, हमारी राजनीति से प्रभावित होकर हमारे संपर्क में आ रहे हैं। इन सभी संघर्षों में पार्टी को नए अनुभव मिल रहे हैं।

3) विस्थापन-विरोधी संघर्ष : राज्य के बल पर साम्राज्यवादियों व दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों ने संसाधनों को लूटने के लिए खनन परियोजनाओं, बड़े बांध, अभयारण्य, मेगा स्टील प्लैंट, थर्मल विद्युत प्लैंट, ओपन कास्ट खदान परियोजनाओं, रेल मार्ग जैसे कई भारी परियोजनाओं और उद्योग स्थापित कर रहे हैं। जल-जंगल-जमीन से जनता को विस्थापित कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमारी पार्टी के नेतृत्व में जनता और पीएलजीए एकजुट होकर उठ खड़ी हुई हैं। जन आंदोलनों व जन प्रतिरोध कार्रवाइयों व छापामार युद्ध आदि रूपों में जनयुद्ध जारी रहा है। छत्तीसगढ़ के कुव्वेमारि खदान, डिलमिलि परियोजना और अभयारण्य के खिलाफ; झारखंड में छोटा नागपुर कास्तकारी कानून (सीएनटी), संथाल परगना कास्तकारी कानून (एसपीटी) में उस राज्य के सरकार द्वारा की जा रही सुधारों, अन्य खदान व परियोजनाओं के खिलाफ, महाराष्ट्र में सुर्जागढ़ आदि खदानों के खिलाफ, तेलंगाना में ओपन कास्ट खदानों व पोलावरम प्रोजेक्ट के खिलाफ,

पाकिस्तान के खिलाफ, सीमा समस्या पर चीन के खिलाफ अंधराष्ट्रवाद और झूठी देशभक्ति को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल इस गुट ने चुनाव के समय 'हिन्दू राष्ट्र की स्थापना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर को स्वायत्तता का अधिकार देने वाली धारा 370 को रद्द करना, सामान्य आचार संहिता लागू करना' - ये सब हमारे एजेण्डे में नहीं है - कहते हुए, 'विकास' ही हमारा एजेण्डा है कहकर जनता को धोखा देकर सत्ता में आया है। लेकिन वह सत्तासीन होने के बाद हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम कर रहा है। इसके तहत देश भर में संघ परिवार के कई ब्राह्मणवादी हिन्दू फासीवादी संगठन सक्रिय हैं। नये संगठन विभिन्न नामों से पैदा हो रहे हैं। ये सब हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लक्ष्य से इस असली एजेण्डा को लागू करने के लिए तीव्र रूप से प्रयास कर रही हैं। इनके देखरेख में गोरक्षा के नाम पर समूचे देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों और दलितों पर 'मास लिंचिंग' (सामूहिक रूप से कुचलकर हत्या करना) बढ़ रहा है और उनलोगों में आतंक का वातावरण पैदा कर रहे हैं। वे आदिवासियों, छात्रों, प्राध्यापकों, महिलाओं आदि तबकों के सदस्यों की हत्या करते हुए बेरोकटोक अत्याचार कर रहे हैं। गांवों और रेलवे स्टेशनों के नामों का हिन्दुत्वकरण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बिहार के शेरपुरा को शिवपुरी के रूप में, मुगलसराई रेलवे स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के रूप में बदला गया है। वर्तमान देश भर में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करना मोदी सरकार के एजेण्डे पर है। उच्चतम न्यायालय भी 'दोनों पक्ष सुलह करने से ठीक होगा' का पुराना सलाह देने के बाद, अभी तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने का दावा करने वाला संघ परिवार, पहलकदमी अपने हाथों में लेकर साजिशपूर्ण तरीके से बाबरी मस्जिद मामले में लड़ने वाले मुसलमानों में शिया और सुन्नियों के बीच फूट डालकर उनमें से अपने दलालों को पैदा कर रहा है। न्याय व्यवस्था का भगवाकरण करने के लिए तीव्र प्रयास करते हुए, अपने फासीवादी शासन को कानूनी वैधता दिलाने में लगे हुए है।

देश में मौजूद इन परिस्थितियों के कारण साम्राज्यवाद-परस्त, पक्की देशद्रोही नीतियों और पुरानी प्रगति-विरोधी नीतियों के साथ ब्राह्मणवादी हिन्दू फासीवाद उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और उत्पीड़ित सामाजिक जनसमुदायों का साझा दुश्मन बन गया है। इसके खिलाफ विभिन्न रूपों में जनप्रतिरोध बढ़ रहा है। यह हमारे देश की राजनीतिक घटनाक्रम में पिछले तीन सालों में आया नया बदलाव है।

करने के कारण मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग के लोगों की जिन्दगियां उथल-पुथल हो रही हैं। लेकिन विश्व आर्थिक संकट के कारण प्रत्याशित रूप से देश के अंदर साम्राज्यवादी निवेश नहीं आने कारण वह सत्ता में आसीन होने के तीन साल पूरा होने के बाद भी मोदी के 'मेक इन इंडिया' में कोई भी प्रगति नहीं है। देश की औद्योगिक क्षेत्र में मंदी की स्थिति जारी है। बेरोजगारी, दैनिक जरूरत के चीजों की महंगाई और कृषि संकट बढ़कर मोदी के तथाकथित 'विकास' के खोखलेपन का भण्डाफोड़ कर रही है। गरीबी उन्मूलन के नाम पर सरकार द्वारा सामने लायी गयी विभिन्न योजनाएं विफल हो गयी है। मोदी सरकार के किसान विरोधी नीतियों से कृषि संकट बढ़ने के कारण हर एक साल 12 हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसपर परदा डालकर किसानों में भ्रम पैदा करने के लिए और चार सालों में किसानों की आमदनी दोगुना करने का दावा करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जैसी झूठी योजनाएं लागू कर सरकार व निजी कंपनियों को बहुत ही अधिक मुनाफें पहुंचा रही है।

साम्राज्यवादी अनुकूल और किसान-विरोधी नीतियों के दुष्परिणामों के वजह से कृषि संकट गहराने के कारण जाट, पटेल, मराठा, कापु जैसी कृषि आधारित 'अगड़ी' जातियां भी लड़ने के लिए मजबूर होने की परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं। अतीत में आरक्षण का खिलाफत करने वाली ये जातियां अभी अपने लिए शिक्षा-नौकरी के क्षेत्रों में आरक्षण की मांग कर रही है।

मोदी सरकार साम्राज्यवादियों व दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों के हितों के लिए 'एक देश, एक कर, एक बाजार' के नाम पर लोगों पर, छोटे व मध्यम किस्म के व्यापारियों पर भारी कर लगाते हुए, राज्यों के अधिकारों का हनन कर, परोक्ष कर नीति में सुधार करते हुए वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू किया है। यह प्रचार कर रही है कि जीएसटी द्वारा सभी चीजों की कीमतें घटाकर लोगों को मदद करेगी। जीएसटी नीति जब से लागू की गयी है तब से लेकर ठोक दरों के सूचकांक घोषित नहीं किया गया है। देश में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। दैनिक चीजों की कीमतों की बढ़ोत्तरी में कोई बदलाव नहीं आयी आया है। दरअसल बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनके दलालों की हितों को पूरा करने के लिए हिंदू फासीवाद द्वारा आर्थिक क्षेत्र में की जाने वाली हमले के तहत ही जीएसटी को देश की जनता पर थोप दिया गया है।

सरकार के खिलाफ उत्पीड़ित लोगों में बढ़ती असंतुष्टि और आक्रोश को भटकाने के लिए, जन आंदोलनों पर पानी फेरने के लिए मोदी-अमित शाह-मोहन भागवत गुट ब्राह्मणवादी हिन्दू फासीवादी विचारधारा को, कश्मीर मसले में

आंध्रप्रदेश में विशाखा बाक्साइट, ओड़िशा में विभिन्न खदान और अभयारण्य के खिलाफ, केरल व तमिलनाडु में विभिन्न अभयारण्य के खिलाफ आंदोलनों को संचालित किया गया है। जनप्रतिरोधात्मक कार्रवाइयों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों व उनके दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग के कंपनियों के करोड़ों रूपयों के संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। क्रांतिकारी आंदोलन के इलाके के बाहर संचालित कुछ विस्थापन-विरोधी आंदोलनों को पार्टी परोक्ष रूप से मदद दे रही है। विभिन्न जन प्रतिरोध मंचों को संगठित करने के लिए मदद दे रही है। देश भर में साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनके दलालों के खिलाफ विस्थापन-विरोधी आंदोलन जारी है। इसके कारण छत्तीसगढ़ के लोहण्डीगुड़ा, धुरली में टाटा और एस्सार स्टील प्लैंट; ओड़िशा के पोस्को परियोजना; आंध्रप्रदेश के विशाखा बाक्साइट आदि जगहों पर विभिन्न खदान व परियोजनाओं का काम स्थगित हो गया है। कुछ परियोजनाओं को शोषक-शासक वर्ग अपने सरकार के भाड़े के पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा जबरन खुलवा रहे हैं और उनमें काम चलाने के लिए पाशविक बल प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी विस्थापन-विरोधी संघर्षों ने देशव्यापी विस्थापन-विरोधी संघर्षों को सही मार्ग दर्शा रही हैं। साम्राज्यवाद-विरोधी, दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग-विरोधी संघर्षों को चलाने में हमें सकारात्मक अनुभव मिला हैं।

4) बोल्शेविकरण अभियान से अनुकूल परिणाम मिल रहा है : हमारी पार्टी द्वारा लागू बोल्शेविकरण अभियान प्रत्याशित दिशा में एक हद तक अनुकूल परिणाम दे रहा हैं। इसके साथ-साथ विभिन्न स्तरों में संचालित फील्ड ट्रेनिंग, नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (एल.टी.पी.) और फौजी नेतृत्व के प्रशिक्षण कार्यक्रम (एम.एल.टी.पी.) द्वारा आंदोलन को कठिन परिस्थिति से उबरने में मदद मिल रही है। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति और महान नक्सलबाड़ी के 50वीं वर्षगांठों के अवसर पर उन अनुभवों को समूचे पार्टी और जनता तक ले जाया गया है और शिक्षित किया गया है। पीएलजीए में पार्टी नेतृत्व को मजबूत करने के लिए विभिन्न छापामार क्षेत्रों में राजनीतिक-सैनिक प्रशिक्षण कैंप चलाया गया है। इस तरह कुछ राज्यों/स्पेशल जोनों में यह अभियान संपन्न हुआ है और कुछ राज्यों/स्पेशल एरियाओं में अभी भी जारी है। इस अभियान के जरिए मिलने वाले अनुभवों से व्यवहार में लगातार यह कोशिश जारी रखना जरूरी है ताकि पार्टी का बोल्शेवीकरण कर सके। इसको ध्यान में रखकर ऊपर से नीचे तक पार्टी कैडरों का कार्य-आचरण दृढ़संकल्प के साथ जारी है। पिछले साल

राज्य/स्पेशल जोन/स्पेशल एरियाओं से एरिया स्तर तक संचालित प्लीनमों में लिए गए निर्णयों और कार्यनीतियों को कार्ययोजना बनाकर दृढ़ता से लागू किया जा रहा हैं।

5) सामाजिक जांच-पड़ताल और वर्ग विश्लेषण : बदलती सामाजिक परिस्थितियों के मुताबिक जनयुद्ध के कार्यनीति को विकसित करने के लक्ष्य से पार्टी के नेतृत्वकारी कैडर द्वारा पिछले साल में की गयी सामाजिक जांच-पड़ताल और वर्ग विश्लेषण में बाकी रह गये और कुछ राज्य/स्पेशल जोन/स्पेशल एरियाओं में उनके पार्टी कमेटियों द्वारा उक्त कार्य को इस साल संचालित किया गया है। पार्टी रणनीति-कार्यनीति और ठोस परिस्थितियों के मुताबिक नयी कार्यनीतियां बना रही हैं। उन्हें लागू करने के लिए पार्टी, पीएलजीए, विभिन्न स्तरों के क्रांतिकारी जन कमेटियों और क्रांतिकारी जनसंगठनों को मजबूत करने का अभियान और शिक्षा अभियान सहित ठोस योजनाएं बनाकर लागू कर रही हैं।

6) सशस्त्र कृषि क्रांति के सुधार कार्यक्रम : सामंतवाद-विरोधी संघर्षों के तहत विभिन्न राज्यों में पार्टी के नेतृत्व में जनता द्वारा जमीन कब्जे के आंदोलनों को संचालित किया गया है। जमींदारों के पास से जब्त किये गये जमीन को खेतिहर गरीब किसानों के बीच वितरित किया गया है। शोषक वर्गों के सत्ता को जहां उखाड़ा गया है, वहां गांव, एरिया और डिविजन स्तर पर आरपीसीयों का गठन कर, उन्हें विकसित करते हुए कृषि क्रांति के सुधारों को लागू किया गया है। क्रांतिकारी जनता दुश्मन के भीषण हमलों के बीच ही, उन्हें प्रतिरोध करते हुए क्रांतिकारी सुधारों को लागू कर हैं। भ्रूण रूप से वैकल्पिक नवजनवादी अर्थ व्यवस्था को विकसित कर रही हैं। छापामार आधारों (गुरिल्ला बेस) को कायम कर रही हैं। लेकिन दुश्मन के भीषण हमले के बीच कुछ छापामार आधार कमजोर हो गये हैं।

गलतियों, कमजोरियों और सीमितताओं से उबरेंगे

नुकसानों को कम करना होगा। शोषक-शासक वर्गों का हमारी पार्टी के विभिन्न स्तरों के नेतृत्व का सफाया कर क्रांति को कुचल डालने का साजिश है। इसे परास्त करना होगा। क्रांतिकारी आंदोलन में जान कुरबान करना जरूरी होता है, लेकिन जनयुद्ध में क्रांतिकारी शक्तियां यथासंभव गैरजरूरी और गैरअनिवार्य नुकसानों को कम कर अपने बलों को बचाते हुए, दुश्मन के बलों का यथासंभव नुकसान करते हुए ही कमजोर स्थिति से मजबूत शक्ति के रूप

निपटने में नाकाम होकर पूरी तरह विफल हो गयी। इस स्थिति में नये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरीकी शासक वर्ग श्वेत अहंकार को उकसा रहा हैं। उस देश में काले लोगों पर, मुसलमानों पर, गैरअमेरीकी प्रवासी लोगों पर रंगभेद के उन्मादी हमले बढ़ रहे हैं।

कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर मौलिक अंतरविरोध - साम्राज्यवाद और उत्पीड़ित राष्ट्रों तथा जनता के बीच का अन्तरविरोध; साम्राज्यवादी/पूंजीवादी देशों में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच का अन्तरविरोध और साम्राज्यवादियों के बीच अन्तरविरोध दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। दुनिया भर में क्रांतिकारी परिस्थितियां और भी अनुकूल होती जा रही है।

अनुकूल क्रांतिकारी परिस्थितियों को इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में क्रांतिकारी आंदोलन, जनवादी आंदोलन, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन तेज हो रहे हैं। पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देशों में मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों के आंदोलन, रंगभेद-विरोधी, धर्मान्धता-विरोधी आंदोलन बढ़ रहे हैं। साम्राज्यवादियों के शोषण और हस्तक्षेप आधारित नीतियों तथा दुराक्रमणकारी युद्धों के खिलाफ एशिया, अफ्रीका और लातीन अमेरीकी महाद्वीपों के लोग संघर्ष कर रहे हैं। फिलस्तीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुर्दिस्तान, येमेन आदि पिछड़े देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन कई सालों से जारी है। पर्यावरण को पूरी तरह ध्वस्त करने वाली साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ विश्व भर में आंदोलन बढ़ रहे हैं। फिलिप्पीन्स, भारत, तुर्की, पेरू आदि देशों में माओवादी पार्टियों के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन साम्राज्यवादियों, बड़े जमींदारों व दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्गों को चुनौती दे रहे है।

घरेलू परिस्थिति : साम्राज्यवादियों के दिशा-निर्देशन में देश में भाजपा नेतृत्वाधीन राजग (एनडीए) सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें पिछले तीन सालों से साम्राज्यवाद-परस्त भूमण्डलीकरण नीतियों को और आक्रामक रूप से लागू कर रही हैं। 'सब के साथ, सब का विकास,' 'मेक इन इंडिया,' 'स्टार्ट-अप इंडिया' के नाम पर मोदी सरकार जो कर रही है वह सिर्फ साम्राज्यवादियों और भारतीय शासक वर्गों द्वारा देश की लूट है। साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशन और भारतीय दलाल कार्पोरेट घरानों ने अपने मर्जी से लूटने और उन्हें बहुत ही अधिक मुनाफें दिलाने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के लिए खोलने, देश के बाजार को साम्राज्यवादी देशों के माल के ढेर लगाने का (डम्पिंग) केन्द्र के रूप में तब्दील

है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में मौजूद तेल और प्राकृतिक गैस भाण्डार और जलमार्गों पर आधिपत्य के लिए चीन और अमेरीका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा एशिया-प्रशांत इलाके में तनाव बढ़ा रही है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवादियों के बीच अंतरविरोधों की तीव्रता के कारण यह इलाका एक मुख्य क्षेत्र के रूप में तब्दील हो गया है।

चीनी सामाजिक-साम्राज्यवाद कई पिछड़े देशों, खासकर लगभग 20 से ज्यादा अरब देशों के प्राकृतिक संसाधनों और बाजारों को लूटने के वजह से उसके साथ अमेरीकी और विभिन्न साम्राज्यवादियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। यूरोप में आधिपत्य के लिए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इस स्थिति में विश्व भर में भौगोलिक-राजनीतिक ध्रुवीकरण बदल रही है।

साम्राज्यवादियों के दुराक्रामक युद्धों के खिलाफ, शोषण और उत्पीड़िन के खिलाफ दुनिया के उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं व जनता द्वारा जारी क्रांतिकारी, जनवादी और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को कुचलने के लिए साम्राज्यवादियों और संबंधित देशों के उनकी दलालों द्वारा फासीवाद लागू किया जा रहा हैं। धर्मोन्माद, रंगभेद, अंधराष्ट्रवाद और युद्धोन्माद को उकसा कर जनता को क्रांतिकारी रास्ते से भटकाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर में कार्पोरेट मीडिया इन भावनाओं से जनता के दिलों को लगातार प्रदूषित कर रही है। दूसरी तरफ जनता का जुझारूपन और लड़ाकू क्षमता पर चोट पहुंचाने के लिए साम्राज्यवाद-प्रायोजित एनजीओ अपनी गतिविधियां पिछड़े देशों में सक्रिय रूप से संचालित कर रही है। उत्पीड़ित वर्ग वर्ग-आधार पर एकताबद्ध न हो जाये - इसके लिए उत्तर-आधुनिकतावाद द्वारा सैद्धांतिक हमले जारी है। प्रचंड-अवाकियान की नयी संशोधनवाद सहित रंगबिरंगे संशोधनवाद, संसदवाद, हमारी देश में गांधीवाद भी जनता को क्रांतिकारी रास्ते से भटकाने के लिए यथासंभव कोशिशें कर रही हैं।

नस्लवाद/रंगभेद के आधार पर फासीवादी विचारधारा को उकसाते हुए अमेरिका और यूरोपीय देशों में दक्षिणपंथी, रूढ़ीवादी (दकियानूसी) और फासीवादी पार्टियां क्रमश: मजबूत होते हुए सत्ता पर काबिज हो रही हैं। जर्मनी में पिछले साल अक्टूबर-नवम्बर महीनों में आयोजित राज्यों के चुनावों में एंजेला मर्केल की पार्टी को हार का मुह देखना पड़ा और फासीवादी रूझान वाली पार्टियां सत्ता पर काबिज हो गयी। अमेरीका में ओबामा द्वारा लागू की गयी कोई भी आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और विदेश नीति अमेरीकी आर्थिक संकट को

में विकसित होने में कामयाब होंगे ताकि क्रांति को सफल बना सके।

दुश्मन द्वारा लागू काउण्टर-गुरिल्ला कार्यनीति (छापामार-विरोधी कार्यनीति) को समझने में हुए गलतियों को सुधारना होगा। दुश्मन अपने बलों को लगातार एल.आई.सी. रणनीति-कार्यनीति में प्रशिक्षण दे रहा है। इसके मुताबिक समयानुसार उसके कार्यनीतियों में तेजी से बदलाव ला रहा है। तेजी से बदलती इन कार्यनीतियों को हमारी पार्टी कमेटियों द्वारा गहराई से अध्ययन नहीं करने के वजह से दुश्मन के बल और कमजोरियों को समझ नहीं पा रही हैं। इसलिए वे दुश्मन के कार्यनीतियों को समयानुसार अध्ययन कर, उनका मुकाबला करने की कार्यनीतियां बनानी होगी। उसके मुताबिक पार्टी कैडरों व पीएलजीए बलों को प्रशिक्षित कर सफलतापूर्वक अपना कार्य को जारी रखना होगा।

कोवर्ट और विश्वासघातियों को पहचानने में निपुणता बढ़ानी होगी। इस तरह के लोगों के बारे में हमेशा जागरूक रहना होगा। सामने आने वाले चीजों पर उचित ध्यान नहीं देने के वजह से गंभीर नुकसानों को झेलने के परिप्रेक्ष्य में इस कमजोरी से तुरंत बाहर आना होगा और इसपर प्रयास करना होगा।

आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या में गिरावट लानी होगी। पार्टी कैडरों में क्रांतिकारी राजनीतिक प्रयास चेतनापूर्वक संचालित कर वर्गघृणा और वर्ग चेतना उनमें बढ़ाना होगा। उन्हें बोल्शेवीकरण करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर आंदोलन और काम की समीक्षा करनी होगी। समस्याओं और गलतियों को कम कर और होने वाले परिणामों को समझते हुए सही दिशानिर्देशन देकर आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या में गिरावट लानी होगी।

जनता में राजनीतिक प्रयास जारी रखने में कमजोरियों को सुधारना होगा। जनता को राजनीतिक रूप से चेतनाबद्ध करने का प्रयास हमारे सभी कार्यों का केन्द्रबिन्दु होना चाहिए। शोषक-शासक वर्गों और एन.जी.ओ. (गैरसरकारी संगठन) के द्वारा बड़े पैमाने पर सामने लाये जाने वाले सुधारों के बारे में, संसदीय चुनावों के बारे में लोगों में लगातार उभरने वाले रंगबिरंगे भ्रमों से उन्हें बाहर लाने का प्रयास करना होगा ताकि जनता में वर्गघृणा और चेतना को बढ़ा कर जन आधार को मजबूत कर सके।

कृषि क्रांति के सुधारों को छापामार युद्ध और क्रांतिकारी राजसत्ता के साथ जोड़ कर संचालित करने में कमजोरियों से उबरना होगा। यानी, राजनीतिक गोलबंदी, हथियारबद्ध कार्रवाइयां और कृषि क्रांति के सुधारों को

समन्वय के साथ संचालित करना होगा।

संगठितीकरण में जारी कमजोरियों से उबरना होगा। विभिन्न आंदोलनों में सामने आने वाले लोगों को विभिन्न जनसंगठनों में संगठित करना, उनलोगों से पार्टी, पीएलजीए और संयुक्त मोर्चा को विकसित करना, भर्ती में वृद्धि लाने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखना होगा। इसमें जारी कमजोरियों को सुधारना होगा।

प्रिय कामरेडो!

इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान अंतरराष्ट्रीय और घरेलू परिस्थिति का आकलन कर उचित कार्यभार लेना जरूरी है।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति : विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अभी भी सकंट के दलदल में फंसी हुई है। इस संकट से निपटने में साम्राज्यवादियों द्वारा लागू सभी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक नीतियां नाकाम रही हैं। दूसरी तरफ, चीन समाजवाद-साम्यवाद का नाम रटते हुए नयी सामाजिक-साम्राज्यवादी देश के रूप में सामने आयी है। इसकी वजह से विश्व आर्थिक संकट और तेज होती जा रही है। चीन बहुत अधिक मात्रा में मुनाफें कमाने के लिए पिछड़े अफ्रीकी, एशियाई और लातीन अमेरीकी देशों के प्राकृतिक संसाधनों और श्रमशक्ति को तीव्र रूप से लूट रही है। अपने बात कबूल नहीं करने वाले चाद (अफ्रीका) जैसे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। विश्व में चीन अपनी प्रभुत्व को विस्तार करने के लिए वियतनाम और फिलिप्पीन्स के दक्षिण और पूर्व चीन सागर के जलक्षेत्रों में, पाकिस्तान और जिबूती जैसे देशों में सैन्य बलों को तैनात करते हुए उनके सम्प्रभुता के लिए खतरा बन रही है। चीनी सामाजिक-साम्राज्यवाद न केवल चीनी जनता का बल्कि दुनिया के उत्पीड़ित राष्ट्रों और जनता का दुश्मन बन गया है।

अमेरीका को फिर से 'महान देश' के रूप में बदलने की बात कर नस्लवाद को उकसाते हुए राष्ट्रपति के रूप में सत्ता में आने के तुरंत बाद ट्रम्प ने सात मुस्लिम देशों पर कई पाबंदियां लागू किया है। एच1बी वीसा कानून को सुधार कर प्रवासी नियमों को कठिन बनाया है। खुले तौर पर पर्यावरण-विरोधी नीतियां लागू कर रहा है। परमाणु हथियार बनाने के बहाने इरान और उत्तर कोरिया पर अंकुश लगाने के लिए तीव्र आर्थिक पाबंदियां लगाने के साथ-साथ उन्हें गंभीर युद्ध चेतावनी दे रहा है। उत्तर कोरिया पर युद्ध के लिए हुंकार भर रहा है। मेक्सिको और क्यूबा जैसे देशों पर राजनीतिक और आर्थिक हमला जारी रखा

है। वेनिजुएला के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हुए सैनिक हमले के लिए तैयारियां कर रहा है।

दरअसल अमेरीकी साम्राज्यवाद 2008 की संकट के कारण और उसकी युद्ध अर्थव्यवस्था पूरे समाज के लिए अधिक बोझ हो जाने के वजह से उसके संसाधन और सिकुड़ जाने के साथ-साथ वह राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से कमजोर हो गया है। अपने आर्थिक संकट के परिस्थिति के मुताबिक आर्थिक क्षेत्र में अमेरीका और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मुताबिक और नाटो गठजोड़ के लिए जिस तरह अतीत में वह बहुत ही अधिक पैसे देती थी, उस तरह अभी आबंटन नहीं कर पा रही है। इस स्थिति में वह नाटो गठजोड़ में पहले जैसी एकजुटता कायम नहीं रख पा रही है। पहले जैसे उसे अपने पक्ष में खड़ा नहीं कर पा रही है। इसके वजह से वह अपनी परिस्थिति को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।

इस स्थिति में साम्राज्यवादी रूस अपनी प्रभावक्षेत्र को कायम रखने की प्रयास कर रही है। डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता में आने के बाद अमेरीका और रूस के बीच कुछ चीजों में सहयोगिता दिखने के कारण ट्रम्प को अमेरीकी शासक वर्ग से गंभीर विरोध का सामना करना पड़ा है। सिरिया, युक्रेइन और इरान आदि रणनीतिक मामलों को ध्यान में रखकर अमेरीका ने रूस पर नये सिरे से प्रतिबंध लगायी है। इसके खिलाफ रूस अमेरीकी राजनयिकों को बड़ी संख्या में अपने देश से वापस भेजने का निर्णय लिया है।

दूसरी तरफ चीन साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर कर आर्थिक क्षेत्र में दुनिया को विभाजित करने के लिए अमेरीका के खिलाफ मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़ा है और एशिया में अपनी पकड़ बढ़ा रही है। वर्तमान वह वन बेल्ट-वन रोड (ओबीओआर) योजना के साथ विश्व आधिपत्य के लिए भाग-दोड़ में जुटी है।

आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में अपनी प्रतिद्वंद्वी साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरने वाली चीन पर चोट पहुंचाने के लिए अमेरीका ने वर्ष 2011 में ही एशिया-केन्द्रित नीति बनायी है। ट्रम्प ने भी इसी नीति को अपनाकर चीन-विरोधी आक्रामकता बढ़ा रहा है। दक्षिण चीन सागर के जलक्षेत्र पर अपने हक के लिए फिलिप्पीन्स के दावे का समर्थन करते हुए हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी फैसले का बहाना बनाकर अमेरीका इस इलाके में अपने मित्र देशों के पक्ष में युद्धपोतों को तैनात करते हुए चीन के साथ तनाव बढ़ा रही